

संस्करण : मुंबई

वर्ष : 11

अंक : 58

पृष्ठ : 8

मूल्य : 2.00

शुक्रवार, 06 मार्च, 2026

मंत्र भारत

हिन्दी दैनिक

मुंबई, लखनऊ, प्रयागराज एवं ग्वालियर से एक साथ प्रकाशित एवं ठाणे, नवी मुम्बई, पालघर, नासिक एवं पुणे से प्रसारित



3 राज्यसभा चुनाव: प्रियंका चतुर्वेदी को क्यों नहीं ... 4 ईरान-अमेरिका-इज़राइल युद्ध देखते देखते ... 7 टी20 वर्ल्ड कप : सेमीफाइनल से पहले ...

संक्षिप्त न्यूज

बंगाल में एसआईआर की जांच का डर, 48 घंटों में 3 लोगों ने आत्महत्या

कोलकाता। राज्य में पिछले 48 घंटों में एसआईआर के फैसले के साये में आठ तीन लोगों ने आत्महत्या कर ली। एक अन्य व्यक्ति की स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के कारण मृत्यु हो गई, जिसके लिए परिवार ने एसआईआर से संबंधित चिंता को जिम्मेदार ठहराया है। मगरहाट के 44 वर्षीय वैन चालक रफीक अली गाजी ने कथित तौर पर मंगलवार रात को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जब उन्हें पता चला कि पिछले शनिवार को प्रकाशित अंतिम मरदाता सूची में उनका नाम 'विचारार्थीन' के रूप में दर्ज है।

रफीक की पत्नी अमीना बीबी ने चुनाव आयोग के खिलाफ उस्ती पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय टीएमसी कार्यकर्ताओं ने शव के साथ विरोध प्रदर्शन किया और बुधवार को कुछ समय के लिए उस्ती-शिराकोल सड़क को अवरुद्ध कर दिया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि रफीक अली गाजी (44) का शव दक्षिण 24 परगना के घोलपारा इलाके में बुधवार सुबह अपने कमरे में फंदे से लटका हुआ पाया गया। उन्होंने कहा, गाजी का नाम सूची में विचारार्थीन श्रेणी में पाया गया। उनके परिवार ने दावा किया कि उस श्रेणी में अपना नाम पाकर वह गंभीर मानसिक तनाव में थे। पुलिस ने कहा कि इससे पहले एक अन्य घटना में जलपाईगुड़ी शहर में मोमो विक्रेता गौरंगा दे (62) को भी मंगलवार सुबह अपने आवास के शौचालय में लटका हुआ पाया गया था।

तृणमूल कांग्रेस ने कहा, एक बार फिर त्रासदी डे की मौत को अंतिम सूची में उनके नाम के गायब होने से जोड़ते हुए, सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने बुधवार को 'एक्स' पर पोस्ट में कहा कि बंगाल में एक बार फिर दिल दहला देने वाली त्रासदी हुई।

'सैन्य संघर्ष समाधान नहीं':

पीएम मोदी ने की रूस-यूक्रेन और ईरान जंग रोकने की अपील कर कहा- संवाद एकमात्र तरीका

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टेब की मौजूदगी में हैदराबाद हाउस में दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान हुआ। इससे पहले फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टेब के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की गई। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायसीना डायलॉग 2026 को संबोधित करते समय रूस और यूक्रेन के बीच चार साल से अधिक समय से जारी हिंसक संघर्ष को खत्म करने की वकालत की। उन्होंने इसके अलावा पश्चिम एशिया में अमेरिका-इसाइल और ईरान के बीच युद्ध को भी जल्द से जल्द समाप्त करने का आह्वान किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संघर्षों को सुलझाने का एकमात्र तरीका संवाद और कूटनीति ही है।

फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टेब के साथ एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'एक स्वस्थ ग्रह हमारी साझा प्राथमिकता है। हमें खुशी है कि इस वर्ष हम फिनलैंड

के साथ मिलकर भारत में विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच की मेजबानी करेंगे। इससे हमारे सतत विकास प्रयासों को नई गति और नए विचार मिलेंगे। भारत



और फिनलैंड दोनों ही कानून के शासन, संवाद और कूटनीति में विश्वास रखते हैं।'

'सैन्य संघर्ष से किसी भी समस्या का समाधान नहीं: पीएम मोदी पीएम मोदी ने आगे कहा कि हम इस बात पर एकमत हैं कि केवल सैन्य संघर्ष से किसी भी समस्या का समाधान नहीं

हो सकता। चाहे यूक्रेन हो या पश्चिम एशिया, हम संघर्ष के शीघ्र अंत और शांति के लिए हर प्रयास का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर भी सहमत

हैं कि बढ़ती वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक संस्थानों में सुधार न केवल आवश्यक है, बल्कि अत्यावश्यक भी है, और आतंकवाद को उसके सभी रूपों में समाप्त करना हमारी साझा प्रतिबद्धता है।

इससे पहले पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए कहा, '13वें फिनलैंड के

राष्ट्रपति के रूप में अपनी पहली भारत यात्रा पर मैं राष्ट्रपति स्टेब का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप जैसे अनुभवी और बेजोड़ नेता का इस वर्ष के रायसीना डायलॉग का चीफ गेस्ट बनना हमारे लिए बहुत सम्मान और खुशी की बात है।'

भारत और फिनलैंड महत्वपूर्ण साझेदार हैं: पीएम मोदी

पीएम मोदी ने आगे कहा कि, 'वर्ष 2026 की शुरुआत में ऐतिहासिक भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता हुआ। ये एग्रीमेंट भारत और फिनलैंड के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग को और प्रबल करेगा। डिजिटल प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा और स्थिरता जैसे क्षेत्रों में भारत और फिनलैंड महत्वपूर्ण साझेदार हैं। नोकिया के मोबाइल फोन और टेलीकॉम नेटवर्क ने करोड़ों भारतीयों को जोड़ा है। फिनलैंड के आर्किटेक्ट के सहयोग से हमने चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया है।'

विपक्ष के नेता अशोक का तंज

'पीएम की आलोचना और गारंटी का जिक्र होंगी राज्य बजट की मुख्य बातें'

बंगलूरु। कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने गुरुवार को राज्य बजट पेश होने से पहले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर तंज कसा। उन्होंने दावा किया सरकार करीब 1.15 लाख करोड़ रुपये कर्ज लेने वाली है और जनता पर नए कर (टैक्स) लगाए जा सकते हैं।

अशोक ने कहा कि बजट में कुछ नया नहीं होगा। उन्होंने कहा, बजट की मुख्य बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना और पांच गारंटी योजनाओं 'शक्ति', 'गृह लक्ष्मी', 'गृह ज्योति', 'युवा निधि' और 'अन्न भाग्य' का कई बार जिक्र होंगी। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया कल यानी 6 मार्च को 2026-27 का राज्य का बजट पेश करने वाले हैं। यह उनका रिकॉर्ड 17वां बजट होगा। उनके पास वित्त विभाग भी है।

अशोक ने कहा कि सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार का बजट शुक्रवार को पेश होगा। केंद्रीय बजट में जहां भारतीयों को जोड़ा है। फिनलैंड के आर्किटेक्ट के सहयोग से हमने चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया है।'

महीने करीब चार नए कर लगाते हैं और अब तक 36 कर लागू कर चुके हैं। अब और कर लगाने के तरीके ढूँढ रहे हैं।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले लोगों से वादा किया था कि गारंटी योजनाएं बिना किसी अतिरिक्त



बोझ के लागू की जाएगी। अशोक ने दावा किया कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल खत्म होने तक राज्य का कुल कर्ज संभवतः छह लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो जाएगा। उन्होंने कहा, सरकार पहले ही वित्तीय अनुशासन तोड़ चुकी है और किसी तरह हालात संभालने की कोशिश कर रही है। उन्होंने यह भी कहा, सिद्धारमैया ने जितना कर्ज लिया है, वह पिछले 12 या 13 मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में लिए गए कुल कर्ज के बराबर है।

गन्ना मजदूरों के लिए व्यापक कानून आवश्यक- उपसभापति डॉ. नीलम गोरहे

मुंबई। राज्य में गन्ना मजदूरों की स्वास्थ्य, आर्थिक और सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए एक व्यापक कानून बनाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही मजदूरों को आवश्यक सामग्री समय पर उपलब्ध हो सके, इसके लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली के माध्यम से तत्काल सहायता प्रदान करने के निर्देश भी दिए जायें। यह मत विधान परिषद की उपसभापति डॉ. नीलम गोरहे ने व्यक्त किया। विधान भवन में गन्ना मजदूरों के कल्याण के लिए किए जा रहे उपायों और उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की समीक्षा के लिए डॉ. गोरहे की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई।

बैठक में सहकार विभाग के प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, गन्ना आयुक्त संजय कोल्हे,

परिवार कल्याण के उपनिदेशक डॉ. आशीष भारती (पुणे) तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। इसके अलावा भारत केंद्र ऑनलाइन के अंतर्गत गन्ना कटाई मजदूर नियामक महासंघ के गोपीनाथ मुंडे भी बैठक में मौजूद थे। उपसभापति डॉ. नीलम गोरहे ने कहा कि गन्ना मजदूरों की विभिन्न समस्याओं का गहराई से अध्ययन कर उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए एक व्यापक कानून तैयार कर प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि गमबूट, विद्युत हार्नेस्टर, दस्ताने और महिला मजदूरों के लिए सैनित्री नैपकिन जैसी आवश्यक सामग्री समय पर उपलब्ध कराने के लिए डीबीटी के माध्यम से आर्थिक सहायता देना अधिक प्रभावी होगा।

खरगे का सरकार पर वार, बोले- पीएम मोदी ने विदेश नीति का सरेंडर कर दिया

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मध्य पूर्व संकट से निपटने के उनके तरीके को लेकर तीखा हमला करते हुए इसे भारत के रणनीतिक और राष्ट्रीय हितों का घोर उल्लंघन बताया और प्रधानमंत्री पर सरकार की विदेश नीति को आत्मसमर्पण करने का आरोप लगाया। एक्स पर एक विस्तृत पोस्ट में, खरगे ने पश्चिम एशिया में बिगड़ती स्थिति और क्षेत्र में फंसे भारतीय नागरिकों की दुर्दशा पर सरकार की प्रतिक्रिया के बारे में कई सवाल उठाए। खरगे ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा भारत के रणनीतिक और राष्ट्रीय हितों का घोर उल्लंघन सबके सामने है। खरगे ने इस बात पर प्रकाश डाला कि



भारत में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा 2026 से निरर्थक लौट रहा एक ईरानी जहाज हिंद महासागर क्षेत्र में

गया। इस पर कोई चिंता या संवेदना व्यक्त नहीं की गई। प्रधानमंत्री मोदी चुप हैं। उन्होंने सरकार की अपनी ही नीतियों पर चुप्पी पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि महासागर नीति और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के 'शुद्ध सुरक्षा प्रदाता' होने की नीतियों पर हमें उपदेश क्यों दे रहे हैं, जबकि आप अपने ही आंगन में हो रही घटनाओं पर प्रतिक्रिया नहीं दे सकते? खरगे ने होर्मुज प्रणालि पर गंभीर असर पड़ सकता है, खासकर तब जब भारत सरकार ने रूसी तेल का आयात रोकने के मानवीय संकट पर प्रकाश डाला। उन्होंने सवाल किया कि होर्मुज की खाड़ी में भारतीय ध्वज वाले 38 वाणिज्यिक अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा 2026 से निरर्थक लौट रहा था, हिंद महासागर क्षेत्र (ई) में टॉरपीडो से हमला किया

मौत हो गई है। ऐसे में कोई समुद्री बचाव या राहत अभियान क्यों नहीं चलाया जा रहा है? उन्होंने भारत की ऊर्जा सुरक्षा और व्यापारिक प्रभावों पर भी चिंता जताई। उन्होंने पूछा कि आप कहते हैं कि कच्चे तेल और अन्य तेल का भंडार सिर्फ 25 दिनों का बचा है। तेल की बढ़ती कीमतों के साथ, हमारी ऊर्जा संबंधी आपातकालीन योजना क्या है, खासकर तब जब भारत सरकार ने रूसी तेल का आयात रोकने की मांग को लाभभंग स्वीकार कर लिया है? खाड़ी देशों के साथ अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं के व्यापार का क्या होगा? उन्होंने खाड़ी क्षेत्र में भारतीय नागरिकों के संबंध में विदेश मंत्रालय के 3 मार्च, 2026 के बयान का भी हवाला दिया।

नीतीश कुमार की दिल्ली में नई पारी, उपेंद्र कुशवाहा बोले- '20 साल बिहार की सेवा की, अब देश की करेंगे'

नई दिल्ली। राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) के प्रमुख और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के राज्यसभा उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा ने गुरुवार को राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद नीतीश कुमार के इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने 20 वर्षों से अधिक समय तक बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की और अब वे दिल्ली की सेवा करेंगे। उन्होंने कहा कि एनडीए के उम्मीदवारों के रूप में, आज 5 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया है... सभी उम्मीदवारों की जीत निश्चित है... नीतीश कुमार (राज्यसभा) जा रहे हैं; यह उनका फैसला है, और सभी उनके इस फैसले की सराहना करते हैं। उन्होंने 20 वर्षों से अधिक समय तक बिहार की सेवा की; अब वे दिल्ली की सेवा करेंगे। बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार ने दो दशकों से अधिक समय तक राज्यसभा के लिए नामांकन

दाखिल किया। उन्होंने पटना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल



किया। इससे पहले आज, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनता दल (युनाइटेड) के प्रमुख नीतीश कुमार के बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल को राज्य के इतिहास का 'स्वर्ण अध्याय' बताया और राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन

दाखिल करने पर राष्ट्रीय राजनीति में उनकी वापसी का स्वागत किया। अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री के

रूप में नीतीश कुमार के 'शानदार' कार्यकाल पर जोर दिया, जिसके दौरान उन्होंने बिहार की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री ने राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इसके

साथ ही, लंबे अंतराल के बाद वे राज्यसभा सांसद के रूप में एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश करेंगे। नीतीश कुमार 2005 से अब तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। उनका कार्यकाल वास्तव में गौरवशाली रहा। यह कार्यकाल मुख्यमंत्री के रूप में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में लिखा जाएगा, जिसने बिहार के विकास के सभी पहलुओं को आकार दिया... विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के रूप में अपने लंबे करियर में उनका कुर्ता कभी कलंकित नहीं हुआ। उनका पूरा जीवन भ्रष्टाचार के आरोपों से मुक्त रहा। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 11 वर्षों तक उन्होंने बिहार की प्रगति में हर तरह से महत्वपूर्ण योगदान दिया, और उन्हीं के नेतृत्व में प्रधानमंत्री मोदी की सभी पहलें बिहार की जनता तक पहुंचीं... वे एक बार फिर राज्यसभा सांसद के रूप में दिल्ली लौट रहे हैं।

गुवाहटी। असम विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के तीन निलंबित विधायक कमलाख्या डे पुरकायस्थ, बसंत दास और शशि कांत दास भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए हैं। इस दलबदल से कांग्रेस की चुनावी रणनीति पर गंभीर असर पड़ सकता है, खासकर तब जब भाजपा नेता कांग्रेस की उम्मीदवार सूची को वंशवाद से जुड़ा बताते हुए लगातार निशाना साध रहे हैं। असम कांग्रेस के तीनों निलंबित विधायक शनिवार को गुवाहाटी स्थित राज्य भाजपा मुख्यालय में राज्य भाजपा अध्यक्ष दिलीप सैंकिया की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हुए। चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस नेताओं का भाजपा में जाना पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। इससे पहले पिछले महीने असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा भी सत्तारूढ़ दल में शामिल

असम चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, 3 निलंबित विधायक भाजपा में शामिल

हो चुके हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा ने बताया कि अन्य पार्टियों, विशेषकर कांग्रेस के नेता और पदाधिकारी भी भाजपा में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे भाजपा की विचारधारा के प्रति अपना समर्थन जता रहे हैं।



मार्गेरिटा ने यह भी कहा कि आगामी चुनावों के लिए कांग्रेस द्वारा जारी 42 उम्मीदवारों की सूची में कोई नया चेहरा नहीं है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने मंगलवार को असम विधानसभा चुनाव के लिए 42 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी।

उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस की सूची में शामिल 42 उम्मीदवारों में से लगभग 20 को पिछले चुनावों में जनता कई बार नकार चुकी है। इससे भाजपा को कोई चिंता नहीं है। इससे पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कांग्रेस की उम्मीदवार सूची की आलोचना करते हुए इसे 'वंशवादी सूची' बताया था। उन्होंने कहा कि भाजपा की सूची में जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी और पार्टी आगामी चुनावों के लिए पूरी तरह तैयार है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार कांग्रेस की सूची में असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोमोई (जोरहाट), बिटुपन सैंकिया (गोलाघाट), अब्दुस सोबाहन अली सरकार (गौरीपुर), मार्कलाइन मारक (गोलाघाट पश्चिम - एसटी), गिरीश बरुआ (बोगाईगांव), महानंदा सरकार (बारपेटा - एससी) और रामेन सिंह राभा (बोको-चायगांव - एसटी) सहित कई उम्मीदवार शामिल हैं।

'जीत के लिए कस लें कर्म', एम. के. स्टालिन का खुला पत्र, तिरुचिरापल्ली में डीएमके बनाएगी चुनावी 'मास्टर प्लान'

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने गुरुवार को द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम (डीएमके) के नेताओं और कार्यकर्ताओं को 9 मार्च को तिरुचिरापल्ली में होने वाले पार्टी के राज्य सम्मेलन में आमंत्रित किया। एक खुले पत्र में एमके स्टालिन ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के लिए कर्म करने का आह्वान किया। स्टालिन ने लिखा कि हमारे नेता कलाइन्गार के प्रिय भाइयों और बहनों, जो हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं, आप में से ही एक द्वारा लिखा गया यह निमंत्रण त्रिची सम्मेलन में है। स्टालिन ने कहा कि मैं आप सभी साथियों को द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम (डीएमके) के भव्य विशेष चुनाव सम्मेलन में देखने के लिए उत्सुकता से यह पत्र लिख रहा हूँ, जो द्रविड़ राजनीति का महान आंदोलन है और वीर योद्धाओं के गढ़

त्रिची में 'स्टालिन का शासन जारी रहे - तमिलनाडु की जीत हो' के विषय पर आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि 9 मार्च को तिरुचिरापल्ली के सिरुगनूर में पार्टी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें पार्टी मुख्यालय से लेकर शाखा इकाइयों तक, पार्टी के सभी स्तरों के लगभग दस लाख पार्टी के कार्यकर्ताओं का भाग लेना होगा। हमारी सारी मेहनत का फल पाने का समय है। उस चुनावी मैदान के लिए खुद को तैयार करने के लिए हम त्रिची के सिरुगनूर में एकत्रित हो रहे हैं। तमिलनाडु वे 3 मंत्री और तिरुचिरापल्ली प्रिंसिपल के विधायक में केएन नेहरू की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि 26 फरवरी को मैंने व्यक्तिगत रूप से सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रत्येक प्रशासक को निमंत्रण पत्र भेजा था।

सीएम धामी सरकार हर मोर्चे पर पास, जीएसडीपीसे रोजगार तक में जबरदस्त उछाल

देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के आर्थिक सर्वेक्षण के सकारात्मक आंकड़ों के सतत विकास और सुशासन की दिशा में राज्य सरकार के निरंतर प्रयासों के परिणाम दर्शाते हैं। विज्ञप्ति में कहा गया है कि उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी), प्रति व्यक्ति आय, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई), स्टार्टअप और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में हुई प्रगति दर्शाती है कि उत्तराखंड विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी (सीएमओ) के अनुसार, मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार रोजगार सृजन, निवेश प्रोत्साहन और जन कल्याण पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्तराखंड को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधान सचिव डॉ. आर.



यह 2.54 लाख करोड़ रुपये था, जो डेढ़ गुना से अधिक की वृद्धि दर्शाता है। उन्होंने कहा कि राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2021-22 में 1,94,670 रुपये थी, जो 2024-25 में बढ़कर 2,73,921 रुपये हो गई है। प्रधान सचिव ने कहा कि 2024-25 में राज्य की विकास दर 7.23 प्रतिशत रही। बहुआयामी गरीबी सूचकांक

2021-22 के 9.7 प्रतिशत से घटकर 2024-25 में 6.92 प्रतिशत हो गया है। श्रम बल सहभागिता दर 2021-22 के 60.1 प्रतिशत से बढ़कर 2024-25 में 64.4 प्रतिशत हो गई है, जो रोजगार में भागीदारी में 4.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) में भी लगातार सुधार हुआ है, जो 2001 में 0.247 से बढ़कर 2017 में 0.684, 2021-22 में 0.718 और 2024-25 में 0.722 हो गया है। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, उन्होंने आगे बताया कि राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की संख्या 2021-22 में 59,798 से बढ़कर 2024-25 में 79,394 हो गई है। एमएसएमई के अंतर्गत रोजगार 2022 में 3,43,922 से बढ़कर 2025 में 4,56,605 हो गया है। राज्य में बड़े उद्योगों की संख्या 2021-22 में 107 से बढ़कर 2024-25 में 128 हो गई है।

ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः

'लाइफ फैक्टर आर्च' से

लाइलाज बीमारियों का इलाज हुआ संभव

आंख की रोगाणु की समस्या

कान से ना सुनाई देने की समस्या

किडनी की समस्या

शुक्ल की समस्या

गंजपन की समस्या

गाल कैंसर व किडनी में स्टोन की समस्या, रिक्तन की समस्या आदि को बड़ी सहजता से 'लाइफ फैक्टर आर्च' के द्वारा ठीक किया जाता है।

अर्चना मिश्रा
मो: 7388351913

मधुमेह से पीड़ित हूँ। मैंने इसे ठीक करने में ही पूरी सतर्कता से ठीक करने का था।

पिता शरद पवार के लिए भावुक हुई सुप्रिया सुले, बोलीं- सोनिया और राहुल गांधी का आभारी हूँ

दिव्यांश

मुंबई(संवाददाता)

एनसीपी-एससीपी सांसद सुप्रिया सुले ने गुरुवार को शरद पवार के राज्यसभा नामांकन का समर्थन करने के लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे और मल्लिकार्जुन खर्गे सहित प्रमुख नेताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। यह निर्णय महा विकास अघाड़ी द्वारा लिया गया था, जो गठबंधन सहयोगियों के बीच एकता का प्रतीक है। सांसद सुले ने पार्टी के साथ खड़े रहने और गठबंधन द्वारा लिए गए निर्णय का समर्थन करने के लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, संजय राउत, आदित्य ठाकरे और मल्लिकार्जुन खर्गे के साथ-साथ कांग्रेस और शिवसेना के नेताओं को धन्यवाद दिया।

सुले ने प्रचारकों से कहा कि मैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, संजय राउत, आदित्य ठाकरे... और मल्लिकार्जुन खर्गे, साथ ही हर उस कांग्रेस नेता का तहे दिल से आभारी हूँ

जो हमारे साथ खड़े रहे, और उन वरिष्ठ शिवसेना नेताओं का जिनके साथ हमने काम किया, और उन सभी का जिन्होंने शरद पवार साहब के साथ छह दशकों तक काम किया। महा विकास अघाड़ी



की ओर से शरद पवार साहब का फॉर्म भरने के उनके फैसले के लिए मैं तहे दिल से उनका आभारी हूँ, और मैं वास्तव में सभी का आभारी हूँ। महाराष्ट्र विधानसभा में वर्तमान विधायी संख्या के आधार पर, सत्तारूढ़ महायुक्ति

गठबंधन के पास उन छह सीटों पर आराम से जीत हासिल करने के लिए पर्याप्त संख्या है। विपक्षी एमवीए गठबंधन - जिसमें कांग्रेस, शिवसेना (यूबीटी) और एनसीपी (शरदचंद्र पवार)

स्तर का आह्वान के बाद आगामी राज्यसभा चुनावों में शरद पवार का समर्थन करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने शुरू में इस सीट पर दावा किया था, लेकिन एनसीपी के साथ समन्वय और महा विकास अघाड़ी के सिद्धांतों का पालन करते हुए पवार का समर्थन किया गया, जो महत्वपूर्ण चुनावों से पहले गठबंधन सहयोगियों के बीच एकता को दर्शाता है।

प्रचारकों से बात करते हुए वडोदरा ने कहा कि हमने राज्यसभा सीट पर दावा किया था क्योंकि हमारी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। इसकी प्रबल मांग थी। हालांकि, एनसीपी के शरद पवार गुट के कई नेताओं ने हमसे संपर्क किया और उद्धव ठाकरे से भी बात की। इनमें शरद पवार सबसे वरिष्ठ हैं... हम महा

विकास अघाड़ी (एमवीए) के सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं। हमारे हाई कमांड ने पवार साहब का समर्थन करने का फैसला किया है। हमें फोन आया है कि मल्लिकार्जुन खर्गे ने पवार साहब का समर्थन करने का फैसला किया है।

शामिल हैं - के पास सातवीं और अंतिम भरणे के उनके फैसले के लिए मैं तहे दिल से उनका आभारी हूँ, और मैं वास्तव में सभी का आभारी हूँ। महाराष्ट्र विधानसभा में वर्तमान विधायी संख्या के आधार पर, सत्तारूढ़ महायुक्ति

हैं तथा पुट-बैक प्रक्रिया भी समयबद्ध रूप से सुनिश्चित की जा रही है। रेलवे यादों में उन ट्रेनों के लिए अलग-अलग सेमिमेंटेशन की व्यवस्था की गई है जो थू ट्रेन होती हैं या जिनमें इंजन परिवर्तन की आवश्यकता होती है।

इससे संचालन में होने वाली अनावश्यक देरी को काफी हद तक कम किया गया है। साथ ही मालगाड़ियों की औसत गति में सुधार, क्यू के कार्य घंटों पर बेहतर नियंत्रण तथा प्रमुख यादों और क्यू बदलने के स्थानों पर होने वाली कंजेशन में कमी भी इस सफलता के प्रमुख कारक रहे हैं।

इन्हीं प्रयासों और प्रभावी समन्वय का परिणाम है कि फरवरी 2026 में रतलाम मंडल ने 41 मिनट की प्रि-डिपार्चर डिटेंशन के साथ भारतीय क्यू लॉबी की नियमित निगरानी की व्यवस्था की गई है, जिससे क्यू को समय पर ड्यूटी के लिए भेजना और समय पर क्यू टिए प्रदान करना संभव हो सका

अजित पवार विमान हादसा: सीआईडी ने तेज की मामले की जांच, वीएसआर कंपनी के अधिकारियों से की पूछताछ; जानें अपडेट

पुणे। महाराष्ट्र अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने गुरुवार को वीएसआर वेंचर्स के बड़े अधिकारियों से पूछताछ की। इसी कंपनी का विमान बारामती में हादसे का शिकार हुआ था, जिसमें उपमुख्यमंत्री अजित पवार की जान चली गई थी। सीआईडी के एक अधिकारी ने इस कार्रवाई की जानकारी दी है। हालांकि, जांच अभी चल रही है, इसलिए उन्होंने ज्यादा विवरण नहीं दिया।

क्या है मामला? 28 जनवरी को पुणे जिले के बारामती एयर स्ट्रिप के पास वीएसआर वेंचर्स का 'लियरजेट 45' विमान क्रैश हो गया था। इस दुखद घटना में अजित पवार और चार अन्य लोगों की मौत हो गई थी। हादसे के बाद बारामती तालुका पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ था। बाद में इस केस की जांच पुणे सीआईडी को सौंप दी गई। जांच एजेंसी यह पता लगा रही है कि क्या इस हादसे के पीछे कोई साजिश थी या यह आपराधिक लापरवाही का मामला है। सूत्रों के मुताबिक, सीआईडी ने इस संबंध में कंपनी को कुछ सवालों की सूची भी भेजी थी।

अब इस मामले में राजनीतिक बयानबाजी भी तेज है। एनसीपी (एसपी) विधायक रोहित पवार ने बुधवार को आरोप लगाया कि कोई वीएसआर वेंचर्स को बचाने की कोशिश कर रहा है।

रिपोर्ट में रनवे पर धुंधले निशान और वहां ढीली बजरी होने की बात भी कही गई है। वहीं, अजित पवार के बेटे जय पवार ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया है। इसमें आरोप लगाया



उन्होंने दावा किया कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एआईबी) की शुरुआती रिपोर्ट ने उनके शक को सही साबित किया है। एआईबी की रिपोर्ट में क्या? एआईबी की 22 पन्नों की रिपोर्ट में बताया गया है कि हादसे के समय की दृश्यता (विजिबिलिटी) बहुत कम थी।

क्या है कि कंपनी के मालिक रोहित सिंह उड़ान के दौरान पायलट की सीट पर सो रहे थे। जय पवार ने रोहित सिंह की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक वीएसआर वेंचर्स के सभी विमानों की उड़ानों पर रोक लगा देनी चाहिए।

फरवरी 2026 में प्रि-डिपार्चर डिटेंशन के मामले में रतलाम मंडल भारतीय रेलवे में प्रथम

रतलाम। पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की हैं। वर्ष के अंतिम चरण में पहुँचते हुए फरवरी 2026 में मंडल ने एक और उल्लेखनीय सफलता अपने नाम की है। रतलाम मंडल ने प्रि-डिपार्चर डिटेंशन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए नई उपलब्धि दर्ज की है। भारतीय रेलवे के उन बड़े मंडलों में, जहाँ प्रतिदिन 100 से अधिक मालगाड़ियों के लिए टीए जारी किए जाते हैं, रतलाम मंडल ने प्रथम स्थान प्राप्त कर पश्चिम रेलवे को गौरवान्वित किया है।

प्रेस विज्ञापित के अनुसार इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए मंडल में क्यू बुकिंग की प्रक्रिया को पूरी तरह आधुनिक बनाया गया है। क्यू बुकिंग में 100 प्रतिशत एफओआईएस-सीएमएस (डफ्रेट ऑपरेशन मैनेजमेंट सिस्टम)

इससे संचालन में होने वाली अनावश्यक देरी को काफी हद तक कम किया गया है। साथ ही मालगाड़ियों की औसत गति में सुधार, क्यू के कार्य घंटों पर बेहतर नियंत्रण तथा प्रमुख यादों और क्यू बदलने के स्थानों पर होने वाली कंजेशन में कमी भी इस सफलता के प्रमुख कारक रहे हैं।

इन्हीं प्रयासों और प्रभावी समन्वय का परिणाम है कि फरवरी 2026 में रतलाम मंडल ने 41 मिनट की प्रि-डिपार्चर डिटेंशन के साथ भारतीय क्यू लॉबी की नियमित निगरानी की व्यवस्था की गई है, जिससे क्यू को समय पर ड्यूटी के लिए भेजना और समय पर क्यू टिए प्रदान करना संभव हो सका

हैं तथा पुट-बैक प्रक्रिया भी समयबद्ध रूप से सुनिश्चित की जा रही है। रेलवे यादों में उन ट्रेनों के लिए अलग-अलग सेमिमेंटेशन की व्यवस्था की गई है जो थू ट्रेन होती हैं या जिनमें इंजन परिवर्तन की आवश्यकता होती है।

इससे संचालन में होने वाली अनावश्यक देरी को काफी हद तक कम किया गया है। साथ ही मालगाड़ियों की औसत गति में सुधार, क्यू के कार्य घंटों पर बेहतर नियंत्रण तथा प्रमुख यादों और क्यू बदलने के स्थानों पर होने वाली कंजेशन में कमी भी इस सफलता के प्रमुख कारक रहे हैं।

इन्हीं प्रयासों और प्रभावी समन्वय का परिणाम है कि फरवरी 2026 में रतलाम मंडल ने 41 मिनट की प्रि-डिपार्चर डिटेंशन के साथ भारतीय क्यू लॉबी की नियमित निगरानी की व्यवस्था की गई है, जिससे क्यू को समय पर ड्यूटी के लिए भेजना और समय पर क्यू टिए प्रदान करना संभव हो सका

सरकारी हॉस्टल में शर्मनाक कांड: सात महीने तक जूनियर छात्रों का शोषण करते रहे सीनियर छात्र; पाँक्सो में केस दर्ज

नाशिक। महाराष्ट्र के नाशिक जिले से एक बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां इगतपुरी में समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाए जाने वाले एक सरकारी हॉस्टल में 10वीं कक्षा के सात छात्रों पर अपने जूनियर छात्रों का शारीरिक शोषण करने का आरोप लगा है। यह मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी छात्रों के साथ-साथ हॉस्टल के अधीक्षक के खिलाफ भी पाँक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।

कक्षा के छात्रों को नशीला पदार्थ देते थे। इसके बाद वे उनके साथ अप्राकृतिक कृत्य करते थे। यह एक अधिकारी ने बताया कि पीड़ित छात्रों ने इस बारे में हॉस्टल अधीक्षक सुधांत दूधसागर को जानकारी दी थी।

लेकिन अधीक्षक ने इस गंभीर मामले पर कोई ध्यान नहीं दिया और न ही कोई कार्रवाई की। इसी लापरवाही के कारण उन्हें भी इस मामले में आरोपी

बनाया गया है। प्रशासन ने शुरू की जांच जिला कलेक्टर आयुष प्रसाद ने इस मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया, '10वीं कक्षा के सात छात्रों और हॉस्टल अधीक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। बाल कल्याण समिति भी इस मामले की जांच कर रही है।' इस घटना के सामने आने के बाद जिला परिषद के समाज कल्याण विभाग के प्रभारी अधिकारी डॉ. संजय शिंदे ने भी अपनी टीम के साथ हॉस्टल का दौरा किया। डॉ. शिंदे की टीम ने मौके पर जांच की और अपनी रिपोर्ट जिला परिषद के सीईओ को सौंप दी है। सीईओ को इस मामले में आगे की जांच करने के लिए कहा गया है। वहीं, पुलिस ने सभी सात आरोपी छात्रों को पकड़कर बाल सुधार ग्रह भेज दिया है। मामले की आगे की जांच जारी है।



सात महीने से चल रहा था घिनौना खेल पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपी छात्र हॉस्टल में रहने वाले पांचवीं से सातवीं

घिनौना खेल पिछले सात महीनों से चल रहा था, लेकिन डर के कारण कोई भी छात्र शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था।

लेकिन अधीक्षक ने इस गंभीर मामले पर कोई ध्यान नहीं दिया और न ही कोई कार्रवाई की। इसी लापरवाही के कारण उन्हें भी इस मामले में आरोपी

बिना टिकट यात्रा के खिलाफ अभियान: पश्चिम रेलवे ने वसूले 191 करोड़ रुपये से अधिक जुर्माना

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। पश्चिम रेलवे ने बिना टिकट और अनियमित यात्रा पर रोक लगाने के लिए अपने नेटवर्क पर व्यापक टिकट जांच अभियान चलाया है। इन सघन अभियानों के दौरान अप्रैल 2025 से फरवरी 2026 के बीच पश्चिम रेलवे ने 191 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला है। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक द्वारा जारी प्रेस विज्ञापित के अनुसार, वरिष्ठ वाणिज्य अधिकारियों की निगरानी में टिकट जांच कर्मचारियों की टीम ने मुंबई उपनगरीय लोकल, लंबी दूरी की मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों, यात्री सेवाओं और विशेष अवकाश ट्रेनों में व्यापक जांच अभियान चलाया। इसका उद्देश्य राजस्व हानि को रोकना और यात्रियों में अनुशासन बनाए रखना है। इस अवधि में लगभग 30 लाख बिना

टिकट या अनियमित यात्रियों (जिसमें बिना बुक किए गए सामान के मामले भी शामिल हैं) को पकड़

अनियमित यात्रा पकड़ी गई और करीब 18.50 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया, जो पिछले वर्ष

मामलों में बिना टिकट या अनियमित यात्रा पकड़ी गई, जिससे 4.28 करोड़ रुपये की वसूली हुई।

अप्रैल 2025 से फरवरी 2026 के बीच मुंबई उपनगरीय खंड में 10 लाख से अधिक मामलों का पता चला और लगभग 50 करोड़ रुपये की वसूली की गई, जिसमें एसी लोकल ट्रेनों में लगाए गए जुर्माने भी शामिल हैं।

एसी लोकल में भी बढ़ी कार्रवाई पश्चिम रेलवे ने एसी उपनगरीय लोकल ट्रेनों में भी विशेष जांच अभियान चलाया। सामान्य टिकट लेकर एसी लोकल में यात्रा करने वालों पर रोक लगाने के लिए बार-बार अचानक जांच की गई। अप्रैल 2025 से फरवरी 2026 के बीच एसी लोकल सेवाओं में 1.16 लाख से अधिक जुर्माने के मामले दर्ज किए गए, जिससे 3.76 करोड़ रुपये की वसूली हुई। यह पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 99 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। पश्चिम रेलवे ने कहा कि यात्रियों को हमेशा वैध टिकट लेकर ही यात्रा करने की सलाह दी जाती है, ताकि रेल सेवाओं में अनुशासन और सुचारु व्यवस्था बनाए रखी जा सके।



गया, जिससे 191 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली हुई। यह पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 42 प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर्शाता है। फरवरी 2026 के दौरान ही लगभग 3 लाख मामलों में बिना टिकट या

की तुलना में 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि है। मुंबई उपनगरीय रेल में भी सख्त जांच मुंबई उपनगरीय रेल खंड में भी सघन टिकट जांच अभियान चलाया गया। फरवरी 2026 में लगभग 87 हजार

पश्चिम रेलवे मुंबई सेंट्रल और अहमदाबाद के बीच चलाएगी दो सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेनें

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

यात्रियों की सुविधा तथा बढ़ती यात्रा मांग को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे मुंबई सेंट्रल और अहमदाबाद के बीच विशेष किराये पर दो सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेनें चलाएगी। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञापित के अनुसार, इन ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार है: 1. ट्रेन संख्या 09027/09028 मुंबई सेंट्रल - अहमदाबाद एसी सुपरफास्ट स्पेशल (02 फेरे) ट्रेन संख्या 09027 मुंबई सेंट्रल - अहमदाबाद स्पेशल शनिवार, 07 मार्च 2026 को मुंबई सेंट्रल से 23:45 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 08:30 बजे अहमदाबाद पहुँचेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09028 अहमदाबाद - मुंबई सेंट्रल स्पेशल सोमवार, 09 मार्च 2026 को अहमदाबाद से 03:00 बजे प्रस्थान करेगी और उसी दिन 11:15 बजे मुंबई सेंट्रल

पहुँचेगी। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, वापी, सूरत, भरुक और वडोदरा स्टेशनों पर ठहरेगी। इस ट्रेन में फर्स्ट एसी, एसी 2-टियर तथा एसी 3-टियर श्रेणी के कोच होंगे।



लेकिन अधीक्षक ने इस गंभीर मामले पर कोई ध्यान नहीं दिया और न ही कोई कार्रवाई की। इसी लापरवाही के कारण उन्हें भी इस मामले में आरोपी

स्पेशल रविवार, 08 मार्च 2026 को अहमदाबाद से 15:10 बजे प्रस्थान करेगी और उसी दिन 21:45 बजे मुंबई सेंट्रल पहुँचेगी। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, वापी, सूरत, भरुक और वडोदरा स्टेशनों पर ठहरेगी। इस ट्रेन में विस्टाडोम, एजिक्यूटिव अनुभूति, एजिक्यूटिव वेयर कांफे तथा एसी वेयर कार कोच होंगे। ट्रेन संख्या 09027 एवं 09028 की बुकिंग 06.03.2026 से तथा ट्रेन संख्या 09021 एवं 09022 की बुकिंग 07.03.2026 से सभी पीआरएस काउंटर्स तथा आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के ठहराव, संरचना एवं समय की विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

मध्य रेल भुसावल मंडल

ई-निविदा सूचना

निविदा सूचना सं.

बीएसएल-एन-एसएनटी-27-2025-26 दिनांक 03.03.2026 (खुली ई-निविदा) भारत के राष्ट्रपति की ओर से और उनके लिए मंडल रेल प्रबंधक (सिगनल एवं दूरसंचार) मध्य रेल, भुसावल द्वारा डिजीटली हस्ताक्षरित ऑन लाईन खुली ई-निविदाएँ पात्र निविदाकर्ताओं से निम्न लिखित कार्य के लिए आमंत्रित की जाती हैं। अक्र:- 1., विवरण:- ई-निविदा सूचना सं. टिप्पणी:- बीएसएल-एन-एसएनटी-27-2025-26 दिनांक 03.03.2026 2. कार्य का नाम:- मध्य रेलवे के भुसावल मंडल में 2027 के कुंभ मेले के संदर्भ में दूरसंचार कार्य के अंतर्गत देवलाही, नासिक रोड, ओटा, खेरवाड़ी और करसे सुकेने स्टेशन पर यात्री सूचना प्रणाली जैसे कोच गाइडेंस डिस्टेंस बोर्ड, ट्रेन इंडिकेशन डिस्टेंस बोर्ड, आउटडोर वीडियो डिस्टेंस (वीडियो वॉल), मन्टीलाइन डिस्टेंस बोर्ड, पीए सिस्टम आदि की व्यवस्था करने का कार्य। 3. कार्य की अनुमानित लागत:- रु. 199020954. 51/- (उन्नीस करोड़ नब्बे लाख बीस हजार नौ सौ चौवन रुपये एवं इकावन पैसे मात्र) 4. निविदा फार्म / बुकलेट की किमत:- नहीं, 5. बयाना राशी:- Rs. 11,45,100.00 /- 6. कार्य पूरा करने का समय:- 8 माह एलओए देने के बाद। 7. निविदा जमा करने की प्रारंभ तिथि:- 11/03/2026, 8. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि और समय:- 25.03.2026 के 15:00 बजे तक। 9. निविदा खुलने की तिथि और समय:- 25/03/2026 के 15:30 बजे (यदि संभव हो तो) 10. वेबसाइट का विवरण/जहा से निविदा सूचना के बारे में पूर्ण जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं।:- www.ireps.gov.in

मंडल रेल प्रबंधक (सि. एवं दू.) भुसावल

खतरनाक व विस्फोटक सामान के साथ यात्रा करना दंडनीय अपराध है

वित्त वर्ष 2025-26 में मध्य रेल, मुंबई मंडल में बिना उचित टिकट के यात्रा करने वाले 16.16 लाख यात्रियों से जुर्माने के रूप में 71.31 करोड़ रुपये वसूले गए

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

अपने वास्तविक यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा प्रदान करने के प्रयास में, मध्य रेल के मुंबई मंडल ने अनधिकृत यात्रा के खिलाफ अपना अभियान तेज कर दिया है। वित्त वर्ष 2025-26 (अप्रैल 2025 से फरवरी 2026) के दौरान, मुंबई मंडल की टिकट जांच टीमों ने उपनगरीय, मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों (एसी लोकल ट्रेनों सहित) में अनियमित यात्रा के 16.16 लाख मामलों का पता लगाया और जुर्माना लगाया, जिससे जुर्माने के रूप में 71.31 करोड़ रुपये वसूले गए। अनियमित यात्रा मामलों की संख्या में 2इ की वृद्धि हुई है, जो पिछले वर्ष के 15.90 लाख मामलों से अधिक है। साथ

ही, पिछले वर्ष वसूल की गई राशि 68.56 करोड़ रुपये से अधिक है, जिसमें 4इ की वृद्धि हुई है। अप्रैल 2025 से फरवरी 2026 की अवधि के लिए मामलों और जुर्माने की राशि का विवरण इस प्रकार है: एसी लोकल ट्रेनों से - 1.10 लाख मामले और 3.51 करोड़ रुपये का जुर्माना प्रथम श्रेणी के डिब्बों से - 1.46 लाख मामले और 4.66 करोड़ रुपये का जुर्माना द्वितीय श्रेणी के डिब्बों से - 11.68 लाख मामले और 58.60 करोड़ रुपये का जुर्माना मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए में अंतर से - 50809 मामले और 2.98 करोड़ रुपये का जुर्माना बिना बुक किए गए सामान से - 1.40 लाख मामले और 1.56 करोड़ रुपये का जुर्माना एसी लोकल ट्रेनें

मध्य रेल 94 एसी लोकल ट्रेनें चलाता है, जिनमें से 14 ट्रेनें इस वर्ष हार्बर लाइन पर शुरू की गईं। एसी लोकल ट्रेनों में विशेष टिकट जांच अभियान के ज़रिए वित्त वर्ष 2025-26 में 1.10 लाख मामले पकड़े गए और 3.51 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया, जिसमें प्रतिदिन औसतन 401 मामले पकड़े गए और 1.27 लाख रुपये की वसूली हुई। इसकी तुलना में पिछले वर्ष 89,799 मामले पकड़े गए थे और 2.96 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया था, जो मामलों की पहचान में 23इ और जुर्माने की वसूली में 18इ की वृद्धि दर्शाता है। फरवरी 2026 फरवरी 2026 के दौरान, अनियमित यात्रा के 1.65 लाख मामले पकड़े गए और जुर्माने के रूप में 8.58 करोड़ रुपये वसूले गए। फरवरी 2026 के लिए मामलों और जुर्माने

की राशि का विवरण इस प्रकार है: एसी लोकल ट्रेनों से संबंधित मामले - 12235 मामले और 38.56 लाख रुपये का जुर्माना प्रथम श्रेणी के डिब्बों से संबंधित मामले - 12651 मामले और 40.13 लाख रुपये का जुर्माना द्वितीय श्रेणी के डिब्बों से संबंधित मामले - 1.13 लाख मामले और 6.68 करोड़ रुपये का जुर्माना मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए में अंतर से संबंधित मामले - 16359 मामले और 99.13 लाख रुपये का जुर्माना बिना बुक किए गए सामान से संबंधित मामले - 10579 मामले और 12.83 लाख रुपये का जुर्माना मुंबई मंडल मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों तथा उपनगरीय ट्रेनों में नियमित रूप से विशेष टिकट जांच अभियान चलाता है, जिससे न केवल अनियमित टिकटों के साथ यात्रा करने वाले यात्रियों का पता

लगाकर उन पर जुर्माना लगाया जाता है, बल्कि दूसरों को बिना टिकट यात्रा करने से रोकने में भी इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। मध्य रेल यात्रियों से अपील करता है कि वे उचित और वैध टिकट खरीदकर यात्रा करें और जिम्मेदारी के साथ यात्रा करें ताकि असुविधा और जुर्माने से बचा जा सके। रेलवे बिना टिकट यात्रा के प्रति अपनी शून्य-सहिष्णुता नीति को दोहराता है और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि यात्रियों को आरामदायक और यात्रापूर्ण यात्रा का अनुभव प्राप्त हो। सुरक्षित यात्रा करें, जिम्मेदारी से यात्रा करें, गरिमा के साथ यात्रा करें।

पश्चिम रेलवे - वडोदरा मंडल

इंजीनियरिंग कार्य के संबंध में

सिगनली कार्य

निविदा सूचना सं. SAT/BRC/25-26/38/SIG-R दिनांक: 02.03.2026

भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से कार्यरत वरिष्ठ डीएसटीई/बडोदरा निविदा सं. SandT_BRC_25-26_38 SIG-R के लिए ई-निविदाएं आमंत्रित करते हैं। बिडर्स बिड बंद होने की तारीख और समय तक उनके प्रमाणित/संशोधित जमा करने को समर्थ रहेंगे, यह निविदा के सामने मेन्सुअल प्रस्तावों की अनुमति नहीं है एवं ऐसे किसी भी प्रकार के मेन्सुअल प्रस्तावों को ध्यान में नहीं लिया जायेगा। (1) कार्य का नाम उचित स्थान सहित: (1) आणंद-गोधरा अनुभाग: रोड अंडर ब्रिज का प्रावधान करके समथार फाटक के 08 नं (LL सं: 2.10, 13, 17, 38, 48, 54A, 64) का निरसन, (2) वडोदरा मंडल: आणंद-गोधरा अनुभाग: आणंद-गोधरा अनुभाग पर पुल सं. 32, 35 और 51 के पुनःनिर्माण, (3) आणंद-गोधरा अनुभाग: उमरठ याई के बीच (ओड और डाकोर के बीच ऐसे पं) कि.मी. 22/2-4 अंतर्गत दो लेन रोड ओवर ब्रिज (ROB) का प्रावधान करने द्वारा लेवल X-ing सं. 23 के निरसन के इंजीनियरिंग कार्य के संबंध में सिगनली कार्य। (2) कार्य की अनुमानित लागत: ₹ 1,85,70,922.90 (3) जमा करने की बयाना राशी: ₹ 2,42,900.00 (4) ई-निविदा जमा करने एवं ई-निविदा खोलने की तिथि एवं समय: दिनांक 26/03/2026 को 15:00 बजे एवं दिनांक 26/03/2026 को 15:30 बजे निविदा खोली जाएगी (5) वेबसाइट का विवरण एवं नोटिस का स्थान जहाँ से विवरण देखे जा सकते हैं आदि: <http://www.ireps.gov.in> वरिष्ठ मंडल संकेत व दूरसंचार अभियंता, द्वितीय वल, एनेक बिल्डिंग, म.रे.प. कार्यालय, पश्चिम रेलवे, प्रतापनगर, वडोदरा-390 004. BRC-384

हम फ़ॉलो करें: twitter.com/WesternRly

राज्यसभा चुनाव: प्रियंका चतुर्वेदी को क्यों नहीं मिला टिकट? संजय राउत ने बताई पूरी कहानी और नंबरों का खेल

मुंबई(संवाददाता)

▶ मंत्र न्यूज

महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। राज्य की सात सीटों पर चुनाव होने हैं और इसी बीच शिवसेना (यूबीटी) ने प्रियंका चतुर्वेदी को दोबारा उम्मीदवार नहीं बनाया है। पार्टी नेता संजय राउत ने गुरुवार को इसके पीछे की वजह और राजनीतिक समीकरणों की पूरी कहानी बताई।

संजय राउत ने कहा कि पार्टी की इच्छा थी कि प्रियंका चतुर्वेदी को फिर से राज्यसभा भेजा जाए, लेकिन राजनीतिक गणित उनके पक्ष में नहीं था। इसके अलावा वरिष्ठ नेता शरद पवार के चुनाव मैदान में उतरने से भी स्थिति बदल गई, जिसके कारण शिवसेना (यूबीटी) के लिए यह सीट लड़ना मुश्किल हो गया। पवार नहीं लड़ते तो चतुर्वेदी को मिलता मौका

राउत ने कहा कि यदि राजनीतिक समीकरण अनुकूल होते और शरद पवार

चुनाव नहीं लड़ते, तो शिवसेना (यूबीटी) निश्चित रूप से यह सीट लड़ती और प्रियंका चतुर्वेदी को दूसरा मौका दिया जाता। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र से



राज्यसभा की सात सीटें अगले महीने खाली हो रही हैं। एमवीए ने शरद पवार को दिया समर्थन बुधवार को कांग्रेस ने घोषणा की कि वह महाराष्ट्र से राज्यसभा की एक सीट के लिए विपक्षी गठबंधन महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के उम्मीदवार के रूप में एनसीपी (एसपी) प्रमुख शरद पवार का समर्थन करेगी। इस फैसले के बाद उम्मीदवार को लेकर चल रही अटकलों

पर विराम लग गया। इस सीट पर कांग्रेस, एनसीपी (एसपी) और शिवसेना (यूबीटी) तीनों ही दल दावा कर रहे थे।



भाजपा उम्मीदवारों पर भी बोले राउत सत्तारूढ़ भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए चार उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, जिनमें पार्टी के महासचिव विनोद तावडे और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले शामिल हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए राउत ने कहा कि आठवले को दोबारा उम्मीदवार बनाना अपेक्षित था, जबकि तावडे की उम्मीदवारी खास ध्यान देने वाली है।

उन्होंने कहा कि तावडे को उम्मीदवार बनाना उनके संगठनात्मक कामों का सम्मान हो सकता है। 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने के बाद उन्होंने पिछले कई वर्षों में पार्टी के लिए काफी काम किया है। ऐसा है विधानसभा का गणित 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा में 230 से अधिक विधायकों के साथ भाजपा के नेतृत्व वाला महायुति गठबंधन अपने सभी उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने की स्थिति में है। इस गठबंधन में एनसीपी और शिवसेना भी शामिल हैं। वहीं विपक्षी एमवीए के पास केवल एक उम्मीदवार को जिताने लायक संख्या है। इस हिसाब से महायुति सात में से छह सीटें जीत सकती है। महाराष्ट्र से जिन राज्यसभा सदस्यों का छह साल का कार्यकाल अप्रैल में समाप्त हो रहा है, उनमें शरद पवार, रामदास आठवले, फौजिया खान, रजनी पाटिल, प्रियंका चतुर्वेदी, धनंजय पाटिल और भागवत कराड शामिल हैं। इन राउत ने कहा कि आठवले को दोबारा उम्मीदवार बनाना अपेक्षित था, जबकि तावडे की उम्मीदवारी खास ध्यान देने वाली होगी।

टीएचआर आहार की गुणवत्ता सुधारने के प्रयास- मंत्री अदिति तटकरे कुपोषण कम करने पर सरकार का विशेष ध्यान

मुंबई।आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को दिए जाने वाले टीएचआर (टेक होम राशन) पोषण आहार की गुणवत्ता और स्वाद बेहतर बनाने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग प्रयास कर रहा है। साथ ही राज्य में कुपोषण की दर को और कम करने पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। यह जानकारी महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने विधान परिषद में दी।

विधान परिषद में सदस्य चित्रा वाघ द्वारा टीएचआर, पोषण आहार और आंगनवाड़ी सेविकाओं से जुड़े मुद्दों पर उठाए गए प्रश्नों का जवाब देते हुए मंत्री तटकरे ने कहा कि केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार अब टीएचआर सूक्ष्म पोषक तत्वों से समृद्ध प्रीमिक्स के रूप में दिया जा रहा है। इसमें निश्चित मात्रा में प्रोटीन और विभिन्न विटामिन बनाए रखने के मानक तय किए गए हैं। इसी के अनुसार 2023-24 से राज्य में यह पद्धति लागू की गई है।

हालांकि कुछ स्थानों से इस प्रीमिक्स के स्वाद को लेकर शिकायतें मिलने के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग ने इसकी

समीक्षा की है। मंत्री तटकरे ने बताया कि पिछले डेढ़ से दो महीनों से इस आहार के नुस्खे में आवश्यक बदलाव करने का काम चल रहा है, ताकि बच्चों को यह भोजन आसानी से स्वीकार्य हो सके। पोषण मूल्य कम किए बिना इसे अधिक स्वादिष्ट बनाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही पहले की तरह सूखा राशन देने की अनुमति देने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध भी किया गया है। आंगनवाड़ी सेविकाओं से जुड़े मुद्दों पर मंत्री तटकरे ने बताया कि पिछले कई वर्षों से लॉबेट स्मार्टफोन की समस्या का समाधान कर दिया गया है। उन्हें 4जी सुविधा उपलब्ध कराई गई है और भविष्य में इसे और बेहतर बनाने के लिए विभाग से अनुरोध भी किया गया है।

उन्होंने बताया कि टीएचआर वितरण के लिए उपयोग किए जा रहे एफआरएस प्रणाली में जनवरी 2026 तक 85 प्रतिशत से अधिक पंजीकरण पूरे हो चुके हैं, जिससे लाभार्थियों को समय पर पोषण आहार

उपलब्ध कराना संभव हो रहा है। मंत्री तटकरे ने यह भी बताया कि राज्य में कुपोषण कम करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है और 11 जिलों में प्रायोगिक परियोजनाएं लागू की जा रही हैं। पिछले तीन वर्षों में कुपोषण की दर में कमी आई है और इसे 0.10 प्रतिशत से कम करने का लक्ष्य रखा गया है। मुंबई जैसे महानगरों में आंगनवाड़ी और बालवाड़ी के बीच अंतर को समझने के लिए 'गैप मैपिंग' सर्वेक्षण किया जा रहा है। साथ ही नगर निगम, एकीकृत बाल विकास सेवा और शहरी विकास विभाग के समन्वय से शहरी क्षेत्रों में भी बच्चों में कुपोषण और मोटापा कम करने के प्रयास किए जायेंगे।

मुंबई जैसे महानगरों में आंगनवाड़ी और बालवाड़ी के बीच अंतर को समझने के लिए 'गैप मैपिंग' सर्वेक्षण किया जा रहा है। साथ ही नगर निगम, एकीकृत बाल विकास सेवा और शहरी विकास विभाग के समन्वय से शहरी क्षेत्रों में भी बच्चों में कुपोषण और मोटापा कम करने के प्रयास किए जायेंगे। मुंबई जैसे महानगरों में आंगनवाड़ी और बालवाड़ी के बीच अंतर को समझने के लिए 'गैप मैपिंग' सर्वेक्षण किया जा रहा है। साथ ही नगर निगम, एकीकृत बाल विकास सेवा और शहरी विकास विभाग के समन्वय से शहरी क्षेत्रों में भी बच्चों में कुपोषण और मोटापा कम करने के प्रयास किए जायेंगे।

जरूरतमंदों को आवास उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध- ग्रामीण विकास मंत्री जयकुमार गोरे राज्य में पिछले वर्ष लगभग 4 लाख घरों का निर्माण पूरा

मुंबई(संवाददाता)

▶ मंत्र न्यूज

मुंबई। देश के प्रत्येक परिवार को घर उपलब्ध कराना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी पहल है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक व्यापक कार्यक्रम लागू किया है कि देश का कोई भी परिवार घर से वंचित न रहे। महाराष्ट्र में भी इस योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है और पिछले वर्ष राज्य में लगभग चार लाख घरों का निर्माण पूरा किया गया। यह जानकारी ग्रामीण विकास मंत्री जयकुमार गोरे ने विधान परिषद में प्रश्नकाल के दौरान दी।

इस संबंध में सदस्य अमोल मिटकरी ने प्रश्न उठाया था। मंत्री जयकुमार गोरे ने बताया कि पिछले वर्ष राज्य में 28 लाख 24 हजार 386 घरों को मंजूरी दी गई, जो देश के इतिहास में सबसे अधिक मंजूरी है। पिछले एक वर्ष में राज्य में 3 लाख 95 हजार 222 घरों का निर्माण पूरा हुआ, जो एक रिकॉर्ड है। वर्तमान में 23 लाख 92 हजार 242 घरों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार द्वारा निधि वितरण के लिए 'सिंगल नोडल एजेंसी' और 'रियल टाइम इंटीग्रेटेड फंड ट्रॉंसफर' प्रणाली लागू किए जाने के कारण कुछ समय तक किस्तों के वितरण में देरी हुई थी। हालांकि अब यह प्रणाली पूरी तरह

शुरू हो जाने से निधि वितरण सुचारू रूप से हो रहा है। राज्य सरकार ने घर निर्माण के लिए मिलने वाली सब्सिडी में अतिरिक्त सहायता देने का निर्णय भी लिया है। केंद्र और राज्य सरकार से मिलने वाली सहायता के साथ-साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्णयानुसार घर निर्माण के लिए अतिरिक्त 50 हजार रुपये दिए जा रहे हैं। इसमें से 35 हजार रुपये निर्माण कार्य के लिए और 15 हजार रुपये घर पर सौर ऊर्जा द्वारा निधि वितरण के लिए 'सिंगल नोडल एजेंसी' और 'रियल टाइम इंटीग्रेटेड फंड ट्रॉंसफर' प्रणाली लागू किए जाने के कारण कुछ समय तक किस्तों के वितरण में देरी हुई थी। हालांकि अब यह प्रणाली पूरी तरह

मिलाकर लगभग 2 लाख 10 हजार रुपये की सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सरकार ने घर निर्माण के लिए आवश्यक रेत मुफ्त उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया है। पात्र लाभार्थियों को दी जाती है। इसके साथ ही भूमिहीन लाभार्थियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय गृह खरीद योजना के तहत जमीन खरीदने के लिए मिलने वाली सब्सिडी 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है। अकोला जिले के बारे में जानकारी देते हुए मंत्री गोरे ने बताया कि जिले को 40 हजार 478 घरों का लक्ष्य दिया गया था, जिसमें से 39 हजार 992 घरों को मंजूरी दी जा चुकी है।

वरोती-भोरडी परियोजनाओं में अनियमितताओं की जांच के बाद कार्रवाई- मृदा एवं जल संरक्षण मंत्री संजय राठौड़

मुंबई।पुणे जिले के वरोती और भोरडी पकॉलेशन तालाब परियोजनाओं के कार्यों के दौरान यदि अवैध खुदाई या किसी प्रकार की अनियमितता की जानकारी प्राप्त होती है, तो उसकी जांच कर दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। यह जानकारी मृदा एवं जल संरक्षण मंत्री संजय राठौड़ ने विधान परिषद में प्रश्नकाल के दौरान दी। इस संबंध में सदस्य अनिल परब ने प्रश्न उठाया था। मंत्री संजय राठौड़ ने बताया कि वरोती और भोरडी दोनों स्थानों के कार्यों को जल संरक्षण निगम द्वारा मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं में आवश्यकता के अनुसार बुनियादी ढांचे और जल निकासी से संबंधित कार्य किए गए हैं। खुदाई के दौरान निकली मिट्टी, पत्थर और अन्य

उपयोगी खनिज सामग्री का उपयोग निर्माण कार्यों के लिए ही करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने बताया कि ये दोनों गांव केंद्र सरकार द्वारा घोषित पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र (इको-सेंसिटिव ज़ोन) में आते हैं। हालांकि केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार कुछ परियोजनाओं को निर्धारित शर्तों के साथ अनुमति दी जाती है। मंत्री राठौड़ ने स्पष्ट किया कि इन दोनों परियोजनाओं का कार्य केंद्र सरकार की अधिसूचना और दिशा-निर्देशों के अनुसार ही किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि इन परियोजनाओं में से एक के लिए आवश्यक वन भूमि के उपयोग की अनुमति भी केंद्र सरकार ने प्रदान की है। इसलिए वर्तमान में सभी कार्य नियमों के अनुसार ही चल रहे हैं।

'सिकल सेल मुक्त महाराष्ट्र' अभियान को मिला गति, 59.62 लाख लोगों की जांच पूरी- स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आंबेडकर

मुंबई।राज्य में आनुवंशिक बीमारी सिकल सेल के खिलाफ चल रहे अभियान को तेजी दी गई है और अब तक 59 लाख से अधिक नागरिकों की जांच की जा चुकी है। शेष जांच 15 मार्च तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। यह जानकारी सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रकाश आंबेडकर ने विधान परिषद में दी। विधान परिषद में सदस्य उमा खापरे द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में मंत्री आंबेडकर ने बताया कि महाराष्ट्र को सिकल सेल मुक्त बनाने के लिए सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। नागपुर अधिवेशन के दौरान आदिवासी बहुल

जिलों के विधायकों के साथ बैठक के बाद एक अलग कार्यबल (टास्क फोर्स) गठित किया गया और उसके तहत 'अरुणोदय' अभियान शुरू किया गया। स्वास्थ्य मंत्री आंबेडकर ने बताया कि 15 जनवरी 2026 से शुरू हुए इस अभियान में 0 से 40 वर्ष आयु वर्ग के 73.84 लाख लोगों की जांच का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 59.62 लाख लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें 1,714 सिकल सेल रोगी और 28,398 सिकल सेल वाहक पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि अभियान से पहले और बाद मिशन मोड में काम कर रही है। नागपुर अधिवेशन के दौरान आदिवासी बहुल

श्री क्षेत्र ज्योतिबा मंदिर परिसर का विकास पर्यावरणीय दृष्टि से किया जाए- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

170 करोड़ रुपये के संशोधित विकास कार्यों को मंजूरी

मुंबई। कोल्हापुर जिले के श्री क्षेत्र ज्योतिबा मंदिर में राज्य ही नहीं बल्कि देशभर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। यह क्षेत्र पर्यावरणीय दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए मंदिर परिसर का विकास पर्यावरण को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए, ऐसा निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिया है। श्री क्षेत्र ज्योतिबा मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्र के लिए कुल 250 करोड़ रुपये की विकास योजना तैयार की गई है। इसमें से 80 करोड़ रुपये के कार्य पहले ही शुरू हो चुके हैं। शेष 170 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को मंजूरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में विधान भवन में आयोजित उच्च स्तरीय समिति की बैठक में दी गई। इस बैठक में उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांतदादा पाटिल, राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, वन मंत्री गणेश नाईक, पर्यटन मंत्री शंभुराज देसाई, शहरी विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाल, विधायक विनय कोरे, विधायक राहुल आवाडे, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) ऑ. पी. गुप्ता, अतिरिक्त

मुख्य सचिव (राजस्व) विकास खारगे, प्रधान सचिव (ग्रामीण विकास) एकनाथ डवले सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ज्योतिबा मंदिर पर्वत क्षेत्र का विकास करते समय बड़ी संख्या में वृक्षारोपण किया जाए और पहले लगाए गए वृक्षों की जीवित रहने की दर बढ़ाने पर भी ध्यान दिया जाए। पर्वतीय क्षेत्र में ठोस कचरा प्रबंधन प्रभावी ढंग से किया जाना चाहिए। मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु अन्नदान करते हैं, इसलिए इसके लिए एक भोजन मंडप (फूड बैंनोपी) विकसित किया जाए, जिसमें अधिकतम श्रद्धालुओं को स्थान मिल सके। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पर्वतीय क्षेत्र के पर्यावरणीय महत्व को ध्यान में रखते हुए यहां की बस्तियों में सीवेज मंत्री चंद्रकांतदादा पाटिल, राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, वन मंत्री गणेश नाईक, पर्यटन मंत्री शंभुराज देसाई, शहरी विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाल, विधायक विनय कोरे, विधायक राहुल आवाडे, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) ऑ. पी. गुप्ता, अतिरिक्त

भी दी। संक्षिप्त विकास योजना कोल्हापुर जिले के पन्हाला तालुका स्थित श्री क्षेत्र ज्योतिबा मंदिर परिसर के विकास के तहत निम्न कार्य किए जाएंगे- ज्योतिबा पर्वत पर पुराने पैदल मार्गों का चौड़ाकरण और मरम्मत पैदल मार्गों के किनारे परियोजनाओं से प्रभावित पेड़ों का पुनः रोपण सीसीटीवी निंत्रण कक्ष, विद्युत निंत्रण कक्ष, पुलिस कक्ष और मंदिर प्रबंधन कार्यालय यमाई देवी मंदिर क्षेत्र में श्रद्धालुओं के लिए सुविधा केंद्र मंदिर के दक्षिणी प्रवेश द्वार की मरम्मत शाहू कालीन हुजूरवाड़ा भवन का संरक्षण कुस्तिरे से गायमुख झील तक पार्किंग सहित पैदल मार्ग का विकास पांच मेगावाट क्षमता के विद्युत उपकेंद्र और सौर ऊर्जा परियोजना श्रद्धालुओं के लिए आवास व्यवस्था, प्राथमिक स्वास्थ्य कक्ष और भोजन मंडप इन विकास कार्यों के माध्यम से मंदिर परिसर को अधिक सुव्यवस्थित, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

डाइवरों की ब्रीथरनालाइज़र जांच अनिवार्य- परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

मुंबई(संवाददाता)

▶ मंत्र न्यूज

मुंबई।महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (एस्टी) ने ड्यूटी के दौरान शराब सेवन पर रोक लगाने और यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए कड़े कदम उठाने का निर्णय लिया है। इसके तहत डिपो में ड्यूटी पर आने वाले सभी चालकों को रोज़ाना अल्कोहॉल टेस्ट मशीन से शराब जांच करना अनिवार्य कर दिया गया है। उचित रिकॉर्ड दर्ज करने के बाद ही चालक को ड्यूटी पर भेजने के निर्देश दिए गए हैं। यह जानकारी परिवहन मंत्री तथा एस्टी निगम के अध्यक्ष प्रताप सरनाईक ने दी। 25 जनवरी 2026 को मंत्री सरनाईक ने मुंबई के परेल बस स्टैंड का अचानक दौरा किया था, जहां कुछ गंभीर अनियमितताएं सामने आई थीं। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने तुरंत एक जांच समिति गठित की और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही ऐसी घटनाएं दोबारा न हों, इसके लिए कड़े उपाय करने को कहा। इसके अनुसार एस्टी प्रशासन ने तीन



के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। साथ ही समिति द्वारा सुझाए गए उपायों को सभी डिपो में तुरंत लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। नए प्रावधानों के अनुसार डिपो में काम पर आने वाले चालकों की नियमित जांच विभाग अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। नए प्रावधानों के अनुसार डिपो में काम पर आने वाले चालकों की नियमित जांच विभाग अधिकारियों के द्वारा की जाएगी। ड्यूटी देने से पहले चालकों की अल्कोहॉल टेस्ट मशीन से जांच करना और उसका रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा। सहायक कार्यशाला अधीक्षक, सहायक

यातायात अधीक्षक, यातायात निरीक्षक, सहायक यातायात निरीक्षक और यातायात नियंत्रक को यह निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं कि चालकों की शराब जांच नियमित रूप से हो रही है या नहीं। डिपो प्रबंधकों को भी इन आदेशों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है। बस मार्ग पर रहने के दौरान चालक को नियंत्रण कक्ष में लॉगबुक दर्ज करना अनिवार्य होगा। पंजीकरण के बाद चालक की फिर से ब्रीथरनालाइज़र जांच की जाएगी और उचित रिकॉर्ड दर्ज होने के बाद ही बस को अगले मार्ग पर भेजा जाएगा। स्टेशन मास्टरों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि यह जांच नियमित रूप से हो। इसके अलावा बस स्टैंड और डिपो क्षेत्र के विश्राम कक्षों में काम करने वाले चालकों, परिचालकों और कर्मचारियों की समय-समय पर अल्कोहॉल टेस्ट मशीन से जांच कर उसका रिकॉर्ड रखना अनिवार्य किया गया है। संबंधित विभागों के अभिभावक अधिकारियों को अपने दौरे के दौरान इन उपायों के क्रियान्वयन की जांच करने के निर्देश

दिए गए हैं। इस संबंध में सतर्कता विभाग समय-समय पर गुप्त निरीक्षण अभियान चलाएगा। यह निरीक्षण कार्यक्रम सड़क निरीक्षण दल, यातायात निरीक्षक, प्रशिक्षण विभाग और सुरक्षा विभाग के माध्यम से लागू किया जाएगा। एस्टी कर्मचारियों में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाएंगे और सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से शराब के दुष्परिणामों के बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही डिपो में 'मद्यपान जनजागरूकता सप्ताह' आयोजित कर चालकों को सौंपी और अन्य कर्मचारियों का मार्गदर्शन किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्य बस स्टैंड, चालक-परिचालक विश्राम गृह और डिपो में शराब सेवन रोकने के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। अतिथि गृह क्षेत्र में स्वच्छता, पेयजल व्यवस्था, राशनी और पंखों जैसी सुविधाओं की जिम्मेदारी भी संबंधित अधिकारियों को सौंपी गई है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने विश्वास व्यक्त किया कि एस्टी प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए शराब सेवन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है और इन उपायों से बस सेवा अधिक सुरक्षित और अनुशासित बनेगी।

पिंपरी-चिंचवड़ नगर निगम के अग्निशमन विभाग में अनियमितताओं की होगी जांच- मंत्री डॉ. उदय सामंत

मुंबई। पिंपरी-चिंचवड़ नगर निगम के अग्निशमन विभाग में रिक्त पदों, अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी करने में कथित अनियमितताओं और अधिकारियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की विस्तृत जांच कराई जाएगी। यदि जांच में कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह जानकारी उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत ने विधान परिषद में दी। विधान परिषद में सदस्यों अभित गोरखे, श्रीकांत भारतीय और उमा खापरे द्वारा उठाए गए ध्यानकर्षण प्रस्ताव का जवाब देते हुए मंत्री डॉ. सामंत ने बताया कि पिंपरी-चिंचवड़ नगर निगम में मुख्य अग्निशमन अधिकारी का पद 31 अक्टूबर 2022 से रिक्त है। उस समय के अधिकारी के सेवानिवृत्त होने के बाद योग्य अधिकारी उपलब्ध न होने के कारण यह पद खाली रहा और इसका

अतिरिक्त प्रभार दूसरे अधिकारी को दिया गया। उन्होंने बताया कि अग्निशमन विभाग के पदों को भरने के लिए 17 अगस्त 2022 को विज्ञापन जारी किया गया था। इसके तहत उप मुख्य अग्निशमन अधिकारी और प्रभागীয় अग्निशमन अधिकारी के दो पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। हालांकि विज्ञापन में इन पदों के लिए कम से कम पांच वर्ष का अनुभव अनिवार्य रखा गया था, इसलिए अनुभव की शर्त पूरी न करने वाले कुछ उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया गया।

मुंबई में वायु प्रदूषण नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई- राज्य मंत्री माधुरी मिसाल

मुंबई।मुंबई में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार गंभीर है और निर्माण परियोजनाओं के लिए तय नियमों को सख्ती से लागू किया जा रहा है। निर्माण स्थलों पर वायु प्रदूषण मापने वाले उपकरण लगाना, धूल नियंत्रण के उपाय करना और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। यह जानकारी राज्य मंत्री माधुरी मिसाल ने विधानसभा में तारांकित प्रश्न के उत्तर में दी। विधानसभा में सदस्य मनीषा चौधरी ने तारांकित प्रश्न के दौरान मुंबई में वायु प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए निर्माण परियोजनाओं पर क्या कार्रवाई की जा रही है, इस संबंध में सवाल उठाया था। इसका उत्तर देते हुए राज्य मंत्री माधुरी मिसाल ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार सभी चालू निर्माण परियोजनाओं में वायु प्रदूषण मापने वाले उपकरण और एलईडी फ्लशर लगाना अनिवार्य किया गया है। मुंबई महानगरपालिका के 16 फरवरी 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार कुल

इस बीच विधान परिषद के सदस्यों ने उप अग्निशमन अधिकारी ऋषिकेश पिचाडे द्वारा जारी किए गए एनओसी और परमिट को लेकर संभावित अनियमितताओं की आशंका जताई है। इस संबंध में पूरे मामले की जांच पिंपरी-चिंचवड़ नगर निगम के आयुक्त या वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कराई जाएगी, ऐसा मंत्री डॉ. सामंत ने बताया। मंत्री डॉ. सामंत ने यह भी स्पष्ट किया कि जांच के बाद यदि कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करने में कोई हिचकिचाहट नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले 1,400 निर्माण परियोजनाओं को अब तक काम बंद करने के नोटिस जारी किए जा चुके हैं। इसके अलावा शहर में बिना अनुमति मलबा (डेब्रिस) फेंकने वालों के खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। मंत्री माधुरी मिसाल ने बताया कि मुंबई में 'मुंबई वायु प्रदूषण शमन योजना 2023' के तहत 25 बिंदुओं वाला नियम लागू किया गया है, जिसके माध्यम से शहर में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं।

सम्पादकीय

युद्ध के बिगड़ते स्वरूप के बीच भारतीयों को वापस लाना चिंता का विषय

ईरान पर इजरायल और अमेरिका के साझा हमले के बाद युद्ध का स्वरूप बिगड़ता जा रहा है और कहना मुश्किल है कि आने वाले दिनों में यह कौन-सी दिशा अख्तियार करेगा। खासतौर पर हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान की ओर से जिस तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, उसमें मध्य-पूर्व के देशों में भी स्थिति चिंताजनक हो रही है।

इस बीच भारत के लिए एक बड़ी फिक्र यह खड़ी हुई है कि अलग-अलग उद्देश्य से मध्य-पूर्व के देशों में गए जो भारतीय फंस गए हैं, उन्हें वहां से सुरक्षित कैसे निकाला जाए।

अमेरिका और इजरायल के साझा हमले के जवाब में ईरान ने इजरायल को निशाना बनाने के साथ-साथ बहरीन, सऊदी अरब, कतर समेत कई देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों पर मिसाइल से हमले किए हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि वहां रहने वाले लोगों के सामने किस तरह की मुश्किलें खड़ी हो रही होंगी। स्वाभाविक ही भारत के सामने बड़ी चिंता उन इलाकों में फंसे भारतीयों को वापस लाने की है।

दरअसल, समूचे पश्चिम एशिया का इलाका इस समय युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो गया लग रहा है। स्वाभाविक ही वहां रह रहे तमाम आम लोगों के सामने खुद को सुरक्षित रखना एक बड़ी चुनौती है। दूसरी ओर, जो लोग दूसरे देशों से वहां गए हैं, वे किसी तरह वहां से निकलने की उम्मीद में हैं। ऐसे में भारत सरकार ने युद्ध प्रभावित देशों से भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए कोशिश शुरू की है, लेकिन ठोस नतीजे के लिए समय रहते कदम उठाना जरूरी है।

सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीएस) ने पश्चिम एशिया में तेजी से बदलते हालात की समीक्षा की और सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि वे घटनाक्रम से प्रभावित भारतीयों की सहायता के लिए जरूरी और व्यावहारिक कदम उठाएं।

सरकार की ओर से आश्वस्त किया गया है कि युद्ध के असर से जुझ रहे देशों में भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित भारतीय दूतावासों से बातचीत की गई है। भारत ने शांति और सुरक्षा के साथ-साथ विवादों के समाधान के लिए संवाद तथा कूटनीति का समर्थन किया है, लेकिन फिलहाल ज्यादा जरूरत इस बात की है कि युद्धग्रस्त इलाकों में फंसे लोगों की सुरक्षित वापसी की प्रक्रिया शुरू की जाए।

गौरतलब है कि ईरान में करीब दस हजार भारतीय नागरिक रहते हैं, जो पढ़ाई और काम करते हैं। वहीं इजरायल में चालीस हजार से ज्यादा भारतीय रहते हैं। इसके अलावा, खाड़ी देशों और पश्चिम एशिया में लगभग नब्बे लाख भारतीय रहते हैं।

इन देशों में सैन्य तनाव बढ़ने और युद्ध का दायरा फैलने की वजह से उड़ान सेवाएं व्यापक पैमाने पर बाधित हुई हैं और बहुत सारे वैसे भारतीय उन जगहों के हवाईअड्डों पर फंसे हुए हैं, जो किसी तरह वतन लौटना चाहते हैं। हालांकि इससे पहले कई बार अलग-अलग देशों में भड़के युद्ध के दौरान भारत ने अपने हजारों नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की है।

मार इस बार सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि युद्ध में शामिल देशों के बीच हमले अपनी पूरी तीव्रता के साथ जारी हैं और आम लोगों के लिए हवाई क्षेत्र बंद है। जब तक हमलों में कमी नहीं आती और यात्री उड़ानों की गुंजाइश नहीं बनेगी, तब तक बचाव अभियान शुरू करना शायद मुश्किल हो। ऐसे में कूटनीतिक पहल और संवाद के सहारे युद्ध प्रभावित इलाकों से भारतीयों की सुरक्षित वापसी का रास्ता निकालने की जरूरत है।

सवाल यह है कि क्या खामेनेई की हत्या के बाद मिडिल ईस्ट पहले जैसा ही रहेगा? इसका साफ उत्तर है- नहीं। आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट में क्या हो सकता है?



रंगोत्सव होली के सियासी और सांस्कृतिक मायने

रंगपर्व होली भले ही भारतीय सभ्यता-संस्कृति से अनुप्राणित है, लेकिन गुलामी काल में यह पाश्चात्य सभ्यता-संस्कृति के सामाजिक दुष्प्रभाव से भी यह अछूती नहीं बची है। आमतौर पर यह रंगोत्सव देश-दुनिया में हंसी ठिठोली का त्योहार समझा जाता है। इस दौरान आमलोगों में रंग-गुलाब खेलने के साथ-साथ मीठे पकवानों, नमकीन मांसाहारों और नशीले पदार्थों के सेवन जैसे (भांग), द्रव्य (शराब) और गैस (गांजा) का प्रयोग बहुतायत में देखने को मिलता है जिससे लोग झूम उठते हैं।

आमतौर पर शुद्ध यानी सेवक पर्व होली आपसी प्रेम और सौहार्द का प्रतीक है, जब घोर दुश्मन भी एक दूसरे के गले मिलने से नहीं हिचकते हैं। बदलते जमाने के अनुरूप लोकपर्व होली का रंगोत्सव भारतीय राजनीति में व्यक्तित्व ब्रांडिंग का भी पर्याय बन चुका है। यह वसंत पर्व अब सामाजिक-राजनीतिक ध्रुवीकरण, सांप्रदायिक तनाव और चुनावी रणनीति का प्रतीक बन गया है। लोकतांत्रिक भारत में यह प्रवृत्ति वर्ष दर वर्ष गहराती जा रही है। खासकर 2026 में ही बिहार, यूपी और अन्य राज्यों में नेताओं के बड़बोले बयानों ने इसे और उभार दिया। इससे

सांप्रदायिक विवाद को भी बढ़ावा मिला। जहां बीजेपी विधायकों और अधिकारियों ने मुस्लिम समुदाय से होली पर घर में रहने या नमाज स्थगित करने की अपील की, जिससे विपक्ष ने ध्रुवीकरण का आरोप लगाया। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हड़दंगियों पर सखी का संदेश दिया, जबकि बिहार में शराबबंदी पर बहस ने इसे राजनीतिक रंग से जोड़ा। कहना न होगा कि अब ये बयान हिंदुत्व के सियासी एजेंडे को मजबूत करने की भरपूर कोशिश दिखाते हैं। इससे चुनावी रणनीति भी प्रभावित होती है। बिहार में राज्यसभा चुनाव के दौर में होली पर नेताओं ने रंग खेलकर वोटों से जुड़ने की कोशिश की। उधर, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के होली बहिष्कार के ऐलान पर बीजेपी ने हिंदू विरोधी करार दिया।

देखा जाए तो ऐसे विवाद आने वाले चुनावों में सामाजिक ध्रुवीकरण का हथियार बन सकते हैं। लिहाजा इन्हें काबू में करने के लिए पुख्ता प्रशासनिक इंतेजाम किये गए हैं। खासकर राज्यों में पुलिस ने सांप्रदायिक तनाव, स्टैंटबाजी और अराजकता रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया। सिर्फ दिल्ली में ही 15, 000 जवान

ईरान-अमेरिका-इज़राइल युद्ध देखते देखते भारत के दरवाजे तक पहुँच गया, दक्षिण एशियाई देशों की चिंता बड़ी

हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर नई चिंता उभर कर सामने आई है क्योंकि अमेरिकी पनडुब्बी ने श्रीलंका के निकट अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में एक ईरानी युद्धपोत को डुबो दिया। इस घटना ने न केवल श्रीलंका बल्कि पूरे दक्षिण एशिया और विशेष रूप से भारत की सामरिक स्थिति पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटना इस बात का संकेत है कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा संघर्ष अब फारस की खाड़ी से निकल कर हिंद महासागर तक पहुंच गया है, जिसके दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं। इस मुद्दे को लेकर राजनीति भी शुरू हो गयी है जहां श्रीलंका के सांसद इस मुद्दे पर अपनी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं वहीं भारत में लोकसभा के विपक्ष ने नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा सवाल पूछा है।

हम आपको बता दें कि ईरान का युद्धपोत डेना बुधवार को उस समय डूब गया जब अमेरिकी पनडुब्बी द्वारा दागा गया जल गोला उससे टकरा गया। यह घटना श्रीलंका के खोज और बचाव क्षेत्र के भीतर अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में हुई। श्रीलंका की नौसेना को युद्धपोत से संकट संदेश प्राप्त हुआ जिसके बाद बचाव अभियान



चलाया गया। श्रीलंकाई नौसेना ने अब तक 87 शव बरामद किए हैं और 32 नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। कई अन्य नाविक अभी भी लापता बताए जा रहे हैं और उनकी खोज के लिए अभियान जारी है। हम आपको बता दें कि यह घटना श्रीलंका के प्रमुख बंदरगाह नगर गाले से लगभग चालीस किलोमीटर दक्षिण में हुई। यह स्थान फारस की खाड़ी से काफी दूर है, जहां ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष चल रहा है। इसलिए इस घटना ने यह संकेत दिया है कि समुद्री संघर्ष का दायरा तेजी से फैल रहा है।

वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक संदेश के माध्यम से कहा है कि दुनिया इस समय अत्यंत अस्थिर दौर में प्रवेश कर चुकी है और आने वाले समय में हालात और कठिन हो

सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि ईरान का युद्धपोत हिंद महासागर में डूबने की घटना यह दर्शाती है कि यह संघर्ष अब भारत के आसपास के समुद्री क्षेत्र तक पहुंच गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसे कठिन

किलोमीटर दूर चल रहा हो, लेकिन उसके प्रभाव अब हिंद महासागर में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे हैं। उन्होंने कहा कि श्रीलंका के तट से लगभग चालीस किलोमीटर दूर इस प्रकार की सैन्य गतिविधि यह दर्शाती है कि वैश्विक शक्तियों का संघर्ष अब इस समुद्री क्षेत्र तक फैल रहा है। श्रीलंकाई सांसद नामल राजपक्षे ने श्रीलंका की सरकार से यह भी सवाल किया है कि क्या उसे इस सैन्य कार्रवाई की पहले से जानकारी थी? उनका कहना है कि सरकार को देश की जनता और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वह इस हमले से पहले अवगत थी या नहीं? उन्होंने कहा कि यदि सरकार को पहले से जानकारी थी तो उसे यह बताना चाहिए कि ऐसी गतिविधि को लेकर कौन से कदम उठाए गए?

उन्होंने यह भी कहा कि यदि श्रीलंका को इस प्रकार की सैन्य गतिविधि की सूचना नहीं दी गई थी तो यह और भी गंभीर विषय है, क्योंकि इससे छोटे देशों की समुद्री संप्रभुता और सुरक्षा पर प्रश्न खड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी बड़े देश की सैन्य कार्रवाई श्रीलंका के आसपास के जल क्षेत्र में होती है तो इस पर खुली चर्चा और पारदर्शिता आवश्यक है। राजपक्षे ने दक्षिण एशियाई देशों

समय में देश को मजबूत और संतुलित नेतृत्व की आवश्यकता होती है, लेकिन सरकार की ओर से स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। उन्होंने कहा कि भारत की सामरिक स्वायत्तता को बनाए रखना इस समय अत्यंत आवश्यक है। दूसरी ओर, श्रीलंका के सांसद नामल राजपक्षे ने इस घटना को अत्यंत गंभीर बताया है और कहा है कि यह केवल श्रीलंका की ही नहीं बल्कि पूरे हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। उनका कहना है कि युद्ध भले ही हजारों

ममता के गढ़ भवानीपुर में भी नंदीग्राम वाला इतिहास दोहराएगा? ऐसा हुआ तो बंगाल चुनाव का पूरा गेम ही बदल जाएगा

महशूर क्रिकेटर और वर्ल्ड कप विजेता टीम के कप्तान कपिल देव ने कहा था कि वेन यू टेस्ट सक्सेस, योर द गेट वांट मोर यानी एक बार सफलता का स्वाद चख लो, तो जीभ (मन) और अधिक मांगती है। कोई खिलाड़ी जो अप्रत्याशित रूप से एक अधिक मजबूत प्रतिद्वंद्वी को हरा देता है तो उसे जायंट किलर कहा जाता है। राजनीति में भी ऐसे ही नाम हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में सुब्रत पाठक कर्नाज में डिंपल यादव को हराया। स्मृति ईरानी जिन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को अमेठी में हराया। केपी यादव ने गुणा में ज्योतिरादित्य सिंधिया को मात दी थी। दिल्ली के पूर्व सीएम आम आदमी पार्टी के सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल को बीजेपी नेता प्रवेश साहिव सिंह वर्मा ने हार का स्वाद चखाया। लेकिन एक ऐसे ही जायंट किलर जिन्होंने 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ने नंदीग्राम से चुनाव लड़कर शिकस्त दी। वो नाम टीएमसी से उसी साल बीजेपी में आए शुभेदु अधिकारी का है। लेकिन पांच साल बाद, संकेत मिल रहे हैं कि शुभेदु 2026 के चुनाव में ममता के कोलकाता

स्थित गढ़ भाबनीपुर से उन्हें चुनौती दे सकते हैं। कभी घनिष्ठ सहयोगी रहे इन दोनों ने नंदीग्राम आंदोलन में साथ काम किया था। ममता के साथ मिलकर सीपीआई (एम) को सत्ता से बेदखल किया था और 2011 में तृणमूल कांग्रेस के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। 2021 के चुनावों से ठीक पहले अधिकारी के भाजपा में शामिल होने के साथ ही दोनों के रिश्ते में दरार आ गई। नीतजतन नंदीग्राम में एक रोमांचक मुकाबले का मंच तैयार हो गया। फिर क्या था वो भी जायंट किलर बन गए हैं। इनमें से एक सीट भाबनीपुर है। एसआईआर की अंतिम मतदाता सूची से पता चलता है कि इस सीट से कम से कम 47,000 नाम हटा दिए गए हैं, जबकि 14,154 नामों पर अभी भी विचार चल रहा है। इनमें से एक सीट भाबनीपुर है। एसआईआर की अंतिम मतदाता सूची से पता चलता है कि इस सीट से कम से कम 47,000 नाम हटा दिए गए हैं, जबकि 14,154 नामों पर अभी भी विचार चल रहा है। नतीजतन, ममता बनर्जी के गढ़ भाबनीपुर में, जहां 267 बूथ

तेज हो रही हैं, और सुवेंदु अधिकारी द्वारा ममता बनर्जी को उन्हीं के गढ़ में चुनौती देने की संभावना पर चर्चा बढ़ती जा रही है।

भवानीपुर में भाजपा के लिए आत्मविश्वास का एक प्रमुख स्रोत पश्चिम बंगाल में हुए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के परिणाम रहे हैं। एसआईआर प्रक्रिया के परिणामस्वरूप 6 करोड़ से अधिक मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं, जबकि 6 लाख नाम अभी भी विचाराधीन हैं। हालांकि इन सभी नाम हटाए जाने से राज्य की सभी सीटें प्रभावित हुईं, लेकिन कुछ सीटें दूसरों की तुलना में अधिक प्रभावित हुईं। इनमें से एक सीट भाबनीपुर है। एसआईआर की अंतिम मतदाता सूची से पता चलता है कि इस सीट से कम से कम 47,000 नाम हटा दिए गए हैं, जबकि 14,154 नामों पर अभी भी विचार चल रहा है। नतीजतन, ममता बनर्जी के गढ़ भाबनीपुर में, जहां 267 बूथ

को भी व्यापक संवाद की भी आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों को मिलकर हिंद महासागर की सुरक्षा पर गंभीर चर्चा करनी चाहिए। उनका कहना है कि अंतरराष्ट्रीय कानून और प्रत्येक देश की संप्रभुता का सम्मान किया जाना चाहिए। यदि बड़े देशों के बीच संघर्ष छोटे देशों के आसपास के समुद्री क्षेत्रों में फैलता है तो इससे पूरे क्षेत्र की स्थिरता प्रभावित हो सकती है।

दूसरी ओर अमरीकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने इस हमले की पुष्टि करते हुए कहा है कि अमेरिकी पनडुब्बी ने अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में मौजूद एक ईरानी युद्धपोत को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई ईरान की सैन्य क्षमता को कमजोर करने के व्यापक अभियान का हिस्सा है। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि ईरान की नौसैनिक शक्ति को सीमित करना उसकी रणनीति का महत्वपूर्ण भाग है।

देखा जाये तो हिंद महासागर में इस प्रकार की सैन्य कार्रवाई के कई महत्वपूर्ण सामरिक निहितार्थ हैं क्योंकि यह क्षेत्र विश्व के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। एशिया, अफ्रीका और पश्चिम एशिया के बीच होने वाला विशाल व्यापार इसी समुद्री मार्ग से गुजरता है। यदि यहां सैन्य तनाव बढ़ता है तो वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति पर सीधा

ममता के गढ़ भवानीपुर में भी नंदीग्राम वाला इतिहास दोहराएगा? ऐसा हुआ तो बंगाल चुनाव का पूरा गेम ही बदल जाएगा

को 2026 के विधानसभा चुनाव में एक संभावित निर्णायक सीट के रूप में पेश कर रही है। हालांकि, अहम सवाल यह है कि क्या सुवेंदु अधिकारी इस निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उभर सकते हैं। हाल के घटनाक्रमों और राजनीतिक संकेतों की एक श्रृंखला से संकेत मिलता है कि इस संभावना पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है, जिसके लिए गहन जांच की आवश्यकता है। भवानीपुर में भाजपा की मजबूत पैठ बनाने की उम्मीद का एक उदाहरण यह है कि सुवेंदु अधिकारी ने अपना वॉर रूम स्थापित करने के लिए इसी निर्वाचन क्षेत्र को चुना है।

वाई 70 में चक्रवर्ती रोड (दक्षिण) स्थित 8/7 के एक मकान के भूतल पर यह विशेष वॉर रूम बनाया गया है। वाई 70 ही क्यों? इसका कारण एक बार फिर यही है कि 2014 में इसी वाई में भाजपा को सबसे बड़ी बढ़त दिलाई थी।

2026 के चुनावों के लिए भाबनीपुर में भाजपा द्वारा अपने उम्मीदवार को अंतिम रूप देने से पहले ही, पार्टी ने जमीनी स्तर पर काम शुरू कर दिया है, जिसके तहत पूरे निर्वाचन क्षेत्र की देवारों पर काल के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। अटकलों को हवा देते हुए,



रंगोत्सव होली के सियासी और सांस्कृतिक मायने

प्रतीक है। यह वसंत ऋतु के आगमन के साथ नई शुरुआत और सामूहिक आनंद का उत्सव है। इससे सामाजिक एकता मजबूत होती है। सच कहें तो रंगों की होली जाति, वर्ग और लिंग की बाधाओं को तोड़ती है, जहां सभी एक-दूसरे को गले लगाते हैं और पुरानी कटुता भुला देते हैं। खासकर ब्रज की लठमार होली जैसी परंपराएं महिलाओं की सशक्तता और कृष्ण-राधा के प्रेम को दर्शाती हैं। यह भाईचारा और सौहार्द का संदेश देती है। जहां तक आध्यात्मिक महत्व की बात है तो होलिका दहन अधर्म पर धर्म की विजय दिखाता है, जो प्रह्लाद की भक्ति से प्रेरित है। यह हिरण्यकश्यप की पुत्र प्रताड़ना से मुक्ति का पर्व है।

वाकई, होली के रंगों में प्रेम (लाल), ज्ञान (पीला) और समृद्धि (हरा) के प्रतीक हैं, जो अद्वैत की भावना जगाते हैं। कृष्ण की लीला से जुड़ी यह भक्ति और आनंद का संगम है। इसमें कृषि और पर्यावरण के लिए भी संदेश है। फसल कटाई के बाद मनाया जाने वाला यह पर्व प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है, जहां होलिका में पौधे भेंट किए जाते हैं। इसके उल्लास से मानसिक स्वास्थ्य स्थापित है और सामूहिक शुद्धि का माध्यम बनता है।

जहां तक सामाजिक प्रभाव की बात है तो यह परंपरा दुश्मनी भुलाने का संदेश देती है, लेकिन सियासत में ध्रुवीकरण बढ़ाती है। नेताओं के रंग लगाने से पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ता है, पर सांप्रदायिक विवाद भी जन्म लेते हैं। होली भारतीय संस्कृति में सामाजिक समरसता, प्रेम और बुराई पर अच्छाई की जीत का

